भारत सरकार

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1

(22 नवम्बर, 2011 को उत्तर दिए जाने के लिए)

जनजातीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी सुविधाएं

1. **श्रीमती विप्लव ठाकुर:**

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में कितने जिलों में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान क्रियान्वित किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार इस योजना के अंतर्गत आगामी दो वर्षों के दौरान और जिलों को शामिल करने का इरादा रखती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कोई विदेशी सहायता प्राप्त की जा रही है; और

(छ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कौन-कौन से देशों से सहायता प्राप्त हुई?

उत्तर

पेयजल और स्वच्छता मंत्री

(श्री जयराम रमेश)

(क) एवं (ख) : संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आवधिक प्रगति रिपोर्टों, निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों, राज्यों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग, क्षेत्र अधिकारियों की योजना, जिला स्तरीय निगरानी और सतर्कता तथा राज्य/ जिला स्तर पर निगरानी समितियों के जरिए कार्यक्रम के निष्पादन तथा कार्यान्वयन की समीक्षा करने की एक व्यापक प्रणाली है। टीएससी के लिए व्यापक वेब-आधारित ऑनलाईन निगरानी व्यवस्था भी है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 2001 जनगणना के अनुसार स्वच्छता कवरेज 21.9% थी। टीएससी के प्रभावी कार्यान्वयन से, मंत्रालय द्वारा संचालित ऑनलाईन निगरानी प्रणाली के जरिए सभी राज्यों द्वारा दी गई प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, अक्तूबर 2011 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण स्वच्छता कवरेज लगभग 74% तक बढ़ी है। समीक्षा में देश के जनजातीय तथा पर्वतीय क्षेत्र भी शामिल हैं।

(ग) : वर्तमान में टीएससी का कार्यान्वयन देश के 607 ग्रामीण जिलों में हो रहा है।

(घ) तथा (ङ) : टीएससी 'मांग सृजित', परियोजना आधारित कार्यक्रम है, इसमें जिले को इकाई माना जाता है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से यह आशा की जाती है कि वे सभी जिलों के लिए टीएससी परियोजनाएं तैयार करें तथा मंजूरी के लिए भारत सरकार को भेजें।

(च) : जी, नहीं।

(छ) : प्रश्न नहीं उठता।

*****